12

अवसंरचना परियोजनाएं

1. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी [एफएमसी]

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयातित कोयले को घरेलू खनन वाले कोयले से प्रतिस्थापित कर **आत्मनिर्भर भारत** को साकार करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 में 1.31 बि.ट. और वित्त वर्ष 2030 में 1.5 बि.ट. का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। कोयला परिवहन का लागत कुशल, तीव्र और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विकास करना देश का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

भविष्य में कोयला निकासी में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय कोयला खानों के पास रेलवे साइडिंग के माध्यम से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी और कोलफील्ड्स में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के साथ–साथ राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना के विकास पर काम कर रहा है।

कोयला मंत्रालय ने खानों में कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यनीति तैयार की है और 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के अंतर्गत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लदान प्रणाली के उन्नयन के लिए कदम उठाए हैं। कोयला हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी) और शीघ्र लदान प्रणाली वाले साइलो को कोयले की क्रशिंग, साइजिंग और त्वरित कंप्यूटर सहायतायुक्त लदान जैसे लाभ होंगे।

कोयला मंत्रालय ने 1040 एमटीपीए क्षमता की 103 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं (95 –सीआईएल, 5– एससीसीएल तथा 3–एनएलसीआईएल) प्रारंभ की हैं, जिनमें से 291 एमटीपीए क्षमता की 31 परियोजनाएं (29–सीआईएल और 2–एससीसीएल) शुरू हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2027–28 तक लागू किया जाना है।

1.2 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत सट्टुपल्ली में नया पर्यावरण अनुकूल सीएचपी (10 मि.ट.) बनाया गया

मैनुअल हस्तक्षेप में कमी के साथ, कोयले की सटीक पूर्व–तौल मात्रा और बेहतर गुणवत्ता का लदान किया जा सकता है। लदान समय में सुधार भारवाहनों की निष्क्रियता को कम करेगा, जिससे उनकी उपलब्धता बढ़ेगी। सड़क नेटवर्क पर भार कम करने से स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है और डीजल की बचत होती है। यह कंपनी, रेलवे और उपभोक्ताओं के लिए चौतरफा फायदे की स्थिति होगी।

1.3 पीएम गति शक्ति के तहत पहलें

कोयला मंत्रालय ने कोयला परिवहन में स्वच्छ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रेल से निकासी में तेजी लाई है और देश में कोयले की सड़क ढुलाई को धीरे धीरे कम करने के लिए नये प्रयास भी शुरू किए हैं। ग्रीनफील्ड कोयला धारी क्षेत्रों में नई ब्रॉड गेज रेल लाइनों के योजनाबद्ध निर्माण, रेल लिंक को नए लदान बिंदुओं तक विस्तारित करना और कुछ मामलों में रेल लाइनों के दोहरीकरण एवं तिहरीकरण से रेल क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने और अवसंरचना संपर्कता परियोजनाओं के एकीकृत नियोजन और समन्वित कार्यान्वयन के उद्देश्य से अक्टूबर 2021 में अवसंरचना के विकास के लिए गति शक्ति– नेशन मास्टर प्लान प्रारंभ किया। यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं को

शामिल करेगा और स्थानिक नियोजन उपकरणों सहित बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।

पीएम गति शक्ति पोर्टल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर (बीआईएसएजी) के सहयोग से नेशन मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है।

- कोयला मंत्रालय ने 100 से अधिक लेयर की पहचान की है और विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ पोर्टल पर मैप किया है। आवश्यकताओं के आधार पर इन डेटा लेयर की निरंतर निगरानी की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी विशेषताओं के साथ आगे की लेयर को जोड़ा जा सकता है कोयला मंत्रालय और सीएमपीडीआई डेटा लेयर को अपलोड करने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बीआईएसएजी–एन के साथ लगातार संपर्क में है
- यह लेयर परियोजनाओं में नियोजन और निष्पादन चरण के दौरान मंत्रालयों से संबंधित सभी आवश्यकताओं पर विचार करके योजना की प्रक्रिया को गति देगा।
- कोयला मंत्रालय ने पोर्टल पर निम्नलिखित लेयर को ऑन–बोर्ड किया है–

  (क) विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ मैप की गई 100 से अधिक डेटा लेयर।

  (ख) 51 लेयर निर्माणाधीन हैं

  (ग) पोर्टल पर 24 लेयर जोड़ने का प्रस्ताव है।

1.4 वर्ष 2023 के दौरान चालू की गई रेलवे परियोजनाएं

(i) **भद्राचलम रोड–सत्तूपल्ली नई बीजी रेल लाइनः** तेलंगाना के असंबद्ध क्षेत्रों तथा कोयला परिवहन को सुगम बनाने के लिए 54 किलोमीटर लंबी नई रेल।

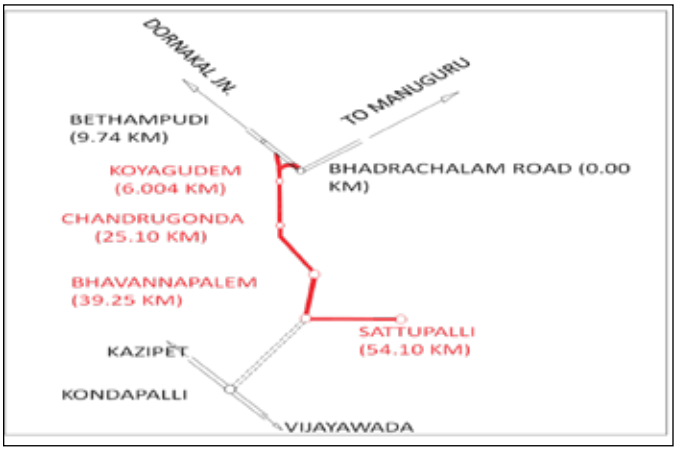

(ii) **पुटागडिया से तेंतुलोई (68 किमी) (ओडिशा में एमसीआरएल रेल कॉरिडोर) तक लिंक के साथ–साथ अंगुल–बलराम–पुटागडिया–जरापाड़ाः** यह रेल लाइन तलचर कोलफील्ड्स को पास के पारादीप और डामरा बंदरगाह से निकटता प्रदान करेगी और समुद्री मार्ग और जहाजों के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी तट के विद्युत संयंत्रों और अन्य उपयोगकर्ताओं को कोयले की आपूर्ति के सस्ते और वैकल्पिक साधन प्रदान करने के लिए इसे उत्तरदायी बनाएगी जिससे आगामी रेल मार्गों में मौजूदा भीड़ से राहत मिलेगी।

(iii) **तोरी–शिवपुर–कठौतिया रेलवे लाइन:** 49 किमी की यह नई रेल लाइन, रेल द्वारा लगभग 125 मि.ट. की कोयला निकासी क्षमता प्रदान करेगी और हावड़ा से दिल्ली तक ट्रंक रेलवे लाइन से कोडरमा, झारखंड होते हुए सड़क द्वारा कोयला परिवहन को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।

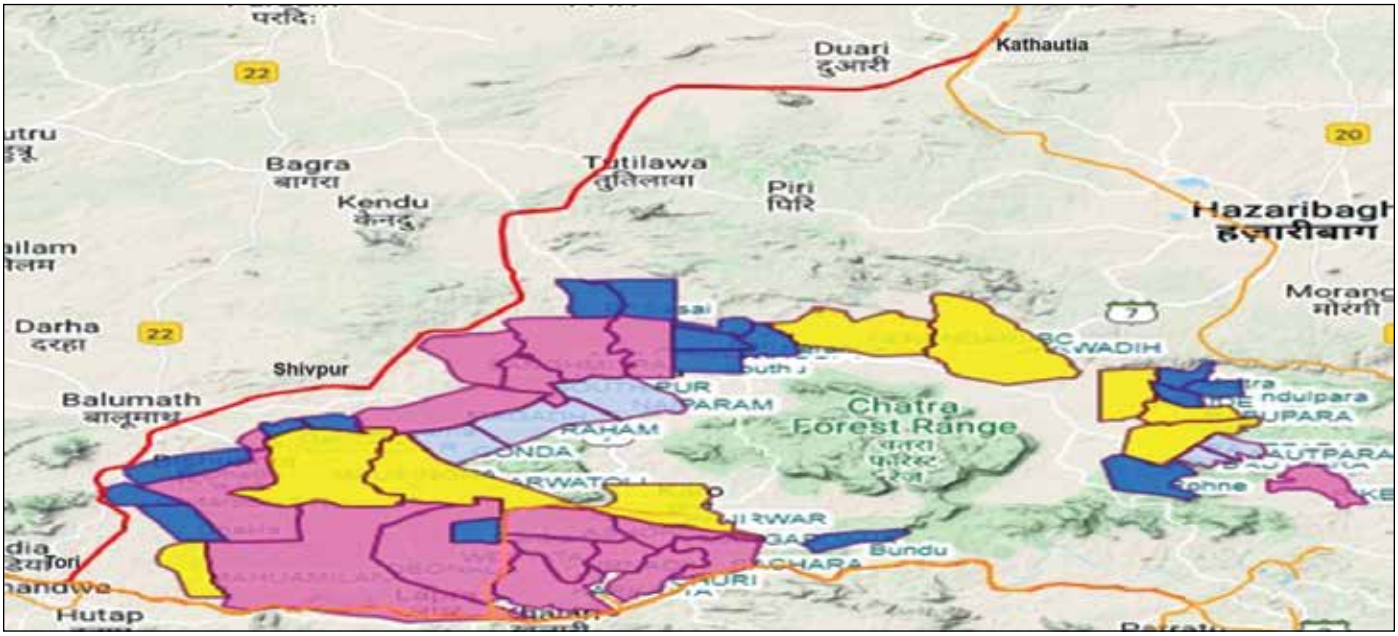

(iv) **सीईआरएल (खरसिया–धरमजयगढ़ रेल लिंक) फेज–1:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 14 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगभग 3,055 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ईस्ट रेल कॉरिडोर चरण–1 को राष्ट्र को समर्पित किया।

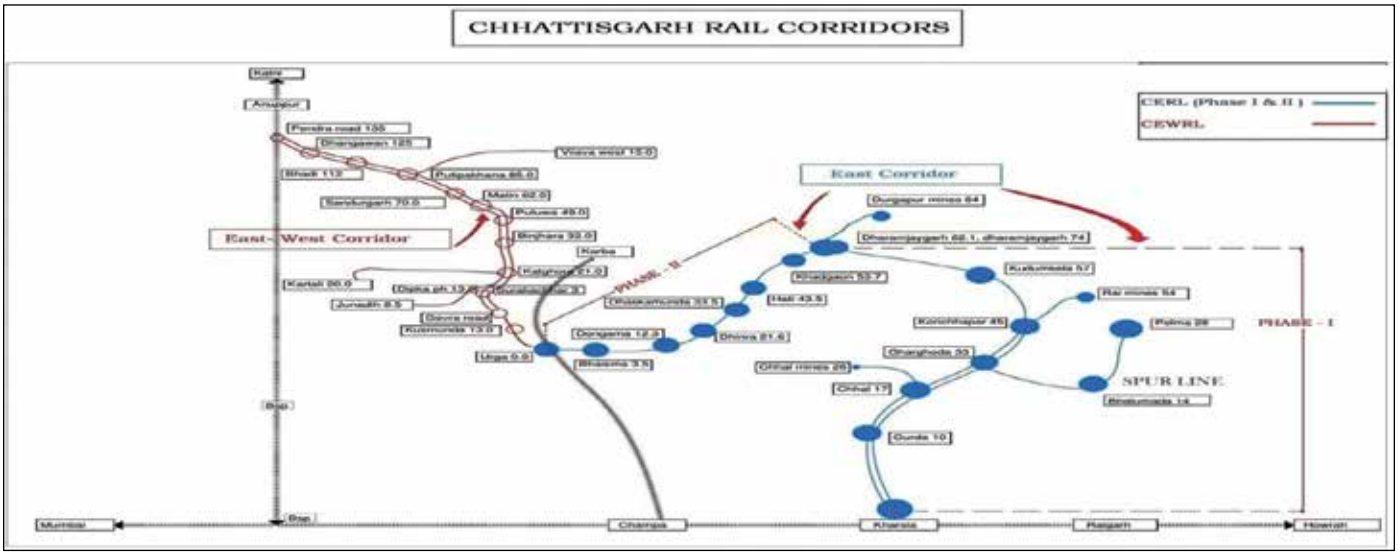

खरसिया और धरमजयगढ़ के बीच 124 किलोमीटर लंबी इस ट्रैक लाइन से रायगढ़ जिले में फैले मंड–रायगढ़ कोलफील्ड की एसईसीएल की कोयला खानों और अन्य कोयला खानों से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं सहित विभिन्न अंत्य उपयोग परियोजनाओं को कोयला और अन्य कच्चे माल के परिवहन में मदद मिलेगी। परियोजना की वार्षिक क्षमता 62 मिलियन टन प्रति वर्ष है।